



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 16, 2017/ज्येष्ठ 26, 1939

No. 152]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 16, 2017/JAIYATHA 26, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2017

प्रकरण सं. एसएसआर 8/2017

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन. गण, यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यूएसए से सोडा एश के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत

फा. सं. 7/5/2017-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी भी कहा गया है) ने चीन जन. गण, यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यूएसए (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी ने दिनांक 17 फरवरी, 2012 के अपने अंतिम जाँच परिणाम सं. 14/17/2010-डीजीएडी द्वारा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। शुल्क को 3 जुलाई, 2012 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 34/2012-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया था।

2. यतः सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1995 की धारा 9 क (5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो उसे लागू किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों के बाद वे निष्प्रभावी हो जाते हैं और

प्राधिकारी के लिए इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है। उक्त के अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने पर पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की आशंका है।

3. यतः मैं. निरमा लि. और मैं. डीसीडब्लू लि. (जिसे आगे याचिकाकर्ता कहा गया है) ने अधिनियम और नियमावली के अनुसार संयुक्त रूप से एक याचिका दायर की है जिसमें चीन जन. गण, यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यूएसए के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए शुल्क को आगे पाँच वर्षों के लिए बढ़ाने की मांग करते हुए "सोडा एश" के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने का अनुरोध किया है।

4. और यतः प्राधिकारी वर्तमान में नियम 23 के अधीन मध्यावधि समीक्षा कर रहे हैं और प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं कि क्या यदि उक्त पाटनरोधी शुल्क को हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है अथवा नहीं।

5. और यतः प्राधिकारी के लिए निर्णायक समीक्षा की जरूरत पर विचार करना अपेक्षित है और यदि वह उससे संतुष्ट होते हैं तो मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने से पहले निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करना अपेक्षित है।

6. और यतः एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन दायर किया गया है जिसमें निर्णायक समीक्षा करने और मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और आवेदन की जाँच से पता चलता है कि निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू करने के लिए पर्याप्त औचित्य है।

क. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

7. विचाराधीन उत्पाद डाइसोडियम कार्बोनेट है जिसे आम तौर पर सोडा एश के रूप में जाना जाता है जिसका रासायनिक सूत्र Na_2CO_3 है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि सोडा एश दो रूपों – लाइट सोडा एश और डेंस सोडा एश में उत्पादित किया जाता है। दो किस्मों में अंतर बल्क घनत्व का है। सोडा एश को सिंथेटिक पद्धति और प्राकृतिक पद्धति से उत्पादित किया जा सकता है, जिसे विलायक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। वर्तमान जाँच में सोडा एश के सभी प्रकार शामिल हैं।

8. सोडा एश डिटरजेंट, साबुनों, क्लीनिंग कंपाउंड, सोडियम आधारित रसायनों, फ्लोट ग्लास, कंटेनर और विशेष ग्लासों, सिलिकेट और अन्य औद्योगिक रसायनों के विनिर्माण में अनिवार्य अवयव है। इसका प्रयोग वस्त्र, कागज, धातु निष्कर्षण उद्योगों और डिसेलीनेशन संयंत्रों में व्यापक रूप से किया जाता है।

9. सोडा एश एक अकार्बनिक रसायन है। इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं. 2836.20 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच पर बाध्यकारी नहीं है।

10. चूंकि वर्तमान जाँच लागू शुल्क की निर्णायक समीक्षा है इसलिए विचाराधीन उत्पादन मूल जाँच में परिभाषित किए गए के समान है।

11. याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि उनके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु, संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापदंडों की दृष्टि से समान वस्तु है। आयातित उत्पाद और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता इनका एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं।

ख. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

12. निर्णायक समीक्षा के लिए अनुरोध मैं. निरमा लि. और मैं. डीसीडब्लू लि. द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आवेदकों ने दावा किया है कि टाटा कैमिकल्स उत्पाद के एक उत्पादक हैं और वह केन्या से उत्पाद के एकमात्र निर्यातक से जुड़े हुए हैं केन्या से आयात मात्रा में काफी अधिक हैं और टाटा कैमिकल्स को मूल जाँच में घरेलू उद्योग नहीं माना गया

था। आवेदकों ने दावा किया है कि टाटा कैमिकल्स को वर्तमान जाँच में भी नियम 2 (ख) के अधीन पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए।

13. केन्या से आयातों की मात्रा, केन्या में उत्पाद के एकमात्र ज्ञात उत्पादक से टाटा कैमिकल्स के संबंध को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर टाटा कैमिकल्स को पात्र घरेलू उद्योग नहीं मानने को उचित समझा है।

14. प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि आवेदकों के उत्पादन का भारत में घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया माना गया है और आवेदक भागीदार कंपनियों को क्षति जाँच के प्रयोजनार्थ नियमावली के नियम 2(ख) के अधीन घरेलू उद्योग माना गया है।

ग. शामिल देश

15. चीन जन. गण, यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यूएसए के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू है। इन देशों से आयातों के संबंध में निर्णायक समीक्षा हेतु अनुरोध किया गया है। वर्तमान निर्णायक समीक्षा केवल चीन जन. गण, यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यूएसए के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर लागू शुल्क को कवर करती है।

घ. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

16. यतः, घरेलू उद्योग द्वारा पाटन के जारी रहने और क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना को साक्ष्यांकित करते हुए सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार इस बात की समीक्षा करेंगे कि क्या संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू शुल्क के समाप्त होने से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और क्या संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के विरुद्ध लागू निश्चयात्मक शुल्क को लागू रखने की आवश्यकता है।

17. प्राधिकारी वर्तमान में दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना फाइल सं. 15/28/2014-डीजीएडी द्वारा शुरू की गई एक मध्यावधि समीक्षा कर रहे हैं जिसमें प्राधिकारी ने अब तक अंतिम निर्धारण नहीं किया है। वर्तमान निर्णायक समीक्षा इस मध्यावधि समीक्षा जाँच के परिणाम के अधीन है।

ङ. प्रक्रिया

18. इस समीक्षा में दिनांक 17 फरवरी, 2012 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 14/17/2010-डीजीएडी जिसमें चीन जन. गण, यूरोपीय संघ, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यूएसए के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश की गई थी, के सभी पहलू शामिल हैं।

19. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

च. जाँच अवधि

20. जाँच की अवधि अप्रैल, 2016 - मार्च, 2017 तक की है। क्षति जाँच अवधि में 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016 और जाँच अवधि की समयावधि शामिल होगी। जाँच अवधि के बाद की अवधि पर भी संभावना के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

ज. सूचना प्रस्तुत करना

21. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 Dgad.india@gov.in

22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति (प्राधिकारी की वेबसाइट www.dgtr.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है) से प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उक्त अनुरोध का अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना होगा।

23. संबद्ध देश के उत्पादक/निर्यातक को प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करते समय, विनिर्माण, उत्पादन और घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री और भारत और अन्य देशों को निर्यात के संबंध में बाजार दशाओं की मौजूदगी को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ, उत्पादक/निर्यातक निम्नलिखित के संबंध में स्पष्टीकरण दे सकते हैं या पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा सकते हैं:

- क) कीमत, लागत, कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।
- ख) उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से आगे लाई गई किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।
- ग) उत्पादक/निर्यातक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।
- घ) विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

समय-सीमा

24. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस समीक्षा जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

I. गोपनीय/अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप से अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

27. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की दो (2) प्रतियां सॉफ्ट प्रतियों के साथ, प्रस्तुत की जानी चाहिए।

28. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।

29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार का उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ब. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

32. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ड. असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डा. इन्द्रजीत सिंह, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2017

Case No. SSR 08/2017

(SUNSET REVIEW)

Subject : Initiation of Sunset review investigation concerning imports of Soda Ash from China PR, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA

F. No. 75/2017-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (herein after referred to as Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of "Soda Ash", (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA (hereinafter referred to as subject Countries). The authority vides its final findings No. 14/17/2010-DGAD dated, 17th February 2012 recommended imposition of anti-dumping duties against dumped imports of the subject goods from the Subject countries. Duties were imposed by the Central Government vide custom notification No. 34/2012-Customs (ADD) dated the 3rd July 2012.

2. Whereas in terms of Section 9A(5) the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantial request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury

3. And whereas, a petition has been jointly filed by M/s Nirma Ltd and M/s DCW Ltd (hereinafter referred to as 'petitioners') in accordance with the Act and the Rules, seeking initiation of a sunset review of the Anti-dumping duty in force on import of "Soda Ash" for extending the duties for a further period of five years, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury of the subject goods originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA.

4. And whereas, the Authority is at present conducting a midterm review under Rule 23 and the Authority has not come to a conclusion whether or not the injury to the domestic industry is likely to continue or recur, if the said anti-dumping duty is revoked.

5. And whereas the Authority is required to consider the need for sunset review and, if satisfied about the same, initiate sunset review before expiry of the existing antidumping duty.

6. And whereas a duly documented application has been filed, requesting sunset review and extension of existing antidumping duty; and examination of the application shows sufficient justification for undertaking sunset review investigations.

A. Product under consideration and like article

7. The product under consideration in the present petition is Disodium Carbonate, popularly known as Soda Ash with chemical formula Na_2CO_3 . The petitioner has stated that the Soda Ash is produced in two forms by the Indian Producers - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is bulk density. Further, Soda Ash can be produced through synthetic route and natural route, known as dissolution process. The present investigation all types of Soda Ash.

8. Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents, soaps, cleaning compounds, sodium based chemicals, float glass, container and specialty glasses, silicates and other industrial chemicals. It is also widely used in textiles, paper, metallurgical industries and desalination plants.

9. Soda Ash is an inorganic chemical. It is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975, falling under the customs sub-heading No. 2836.20. The customs classification is, however, indicative and not binding on the scope of the present investigation.

10. Present investigation, being a sunset review of the duty in force, the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation.

11. Petitioners have submitted that the subject goods produced by them are like article to the goods imported from the subject countries in terms of physical and technical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The imported products and the domestically produced goods are technically and commercially substitutable, and consumers use them interchangeably.

B. Domestic Industry & Standing

12. The request for the sunset review has been filed by M/s Nirma Ltd and M/s DCW Ltd. The applicants have claimed that Tata Chemicals is one of the producers of the product and is related to the sole exporter of the product from Kenya. Imports from Kenya are quite significant in volume and Tata Chemicals was not treated as a domestic industry in the original investigations. The applicants have claimed that Tata Chemicals should not be treated as eligible domestic industry under Rule 2(b) for the present investigation also.

13. Having regard to the volume of imports from Kenya, relationship of Tata Chemicals with the sole known producer of the product in Kenya, the Authority has considered it appropriate not to treat Tata Chemicals as eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b).

14. The Authority has determined that the production by the applicants account for a major proportion in the production of the subject goods by the domestic industry in India. The application is deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry and the applicant participating companies have been treated as the domestic industry under Rule 2(b) of the Rules for the purpose of injury investigation.

C. Countries Involved

15. Antidumping duties are in force on imports of the product under consideration originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA. The request for sunset review is in respect of imports from these countries. The present sunset review covers the duty in force on the subject goods originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA only (collectively referred to as subject countries).

D. Initiation of Sunset Review

16. Having satisfied, on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry, substantiating the likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury, the Authority hereby initiates an investigation in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 of Anti-dumping Rules, to review whether cessation of the duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries, shall lead to continuation or recurrence of dumping of the subject goods from the subject countries and continuation or recurrence of injury to the domestic industry, and need for continued imposition of the definitive duty in force against the subject goods originating in or exported from the subject countries.

17. The Authority is at present conducting a midterm review, initiated vide notification File No. 15/28/2014-DGAD dated 21st July, 2015 where the Authority has not made final determination so far. The present sunset review is subject to the outcome of this midterm review investigations.

E. Procedure

18. The review will cover all aspects of Final Finding Notification No. . 14/17/2010-DGAD dated, 17th February 2012 recommending imposition of anti-dumping duty on import of Soda Ash originating in or exported from China PR, European Union, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA.

19. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rule supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

F. Period of investigation (POI)

20. The period of investigation is April 2016 – March 2017. The injury investigation period shall cover the periods 2013-14, 2014-15, 2015-16 and the period of investigation. The period after the investigation period may also be considered for the purpose of likelihood analysis.

G. Submission of Information

21. The known exporters in the subject countries, the Governments of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building,
5 Parliament Street, New Delhi -110001. Dgad.india@gov.in

22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner (downloadable from the website of the authority at www.dgtr.gov.in) within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

23. While submitting the questionnaire response, producers/exporters in the subject countries may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacture, production, and sales of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may provide sufficient information on the following:

- a. Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labour, output, sales and investment, are without significant state interference and weather cost of major inputs substantially reflect market value.
- b. Production costs and financial situation does not suffer for any distortion.
- c. The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.
- d. Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

H. Time limit

24. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to impose the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation

I. Submission of Information on Confidential/Non-Confidential basis

26. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

27. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

28. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such Information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

J. Inspection of Public File

32. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

K. Non-cooperation

33. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr.INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority